

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति के बाद के संपादित पाठ
प्रेस कॉन्फ्रेंस: 5 अगस्त 2026 (बुधवार)

भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रतिनिधि:

श्री संजय मल्होत्रा - गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री स्वामीनाथन जे - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
डॉ. पूनम गुप्ता - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री शिरीश चंद्र मुर्मू - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री रोहित जैन - उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री संजय कुमार हांसदा - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री इंद्रनील भट्टाचार्य - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री रवि शंकर - कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक

मॉडरेटर:

श्री ब्रिज राज - मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक

ब्रिज राज:

सभी को शुभ दोपहर। इस मौद्रिक नीति के बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए तीसरी है, मैं आपका स्वागत है। हमारे साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा; उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे; डॉ. पूनम गुप्ता; श्री शिरीश चंद्र मुर्मू; और श्री रोहित जैन हैं। हमारे साथ कार्यपालक निदेशक श्री संजय कुमार हांसदा; श्री इंद्रनील भट्टाचार्य; और पहली बार श्री रवि शंकर भी हैं।

मैं भारतीय रिज़र्व बैंक के अन्य सहकर्मियों का भी स्वागत करता हूँ। सर, मीडिया से 26 प्रतिभागी हैं। और हम शुरू करने से पहले, हमारे पास दो आंतरिक घोषणाएं हैं। पहली, मैं मीडिया प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूँ कि कृपया केवल एक प्रश्न पूछें। मैं दोहराता हूँ, केवल एक प्रश्न, ताकि सभी को मौका मिले। दूसरी, मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि कृपया बोलते समय माइक्रोफोन चालू करें, ताकि जो लोग लाइव प्रसारण देख रहे हैं, वे स्पष्ट रूप से सुन सकें। और एक बार जब आप बोलना समाप्त कर लें, तो कृपया माइक्रोफोन बंद कर दें। सर, आपकी अनुमति से, मैं अब नाम बुलाऊंगा।

संजय मल्होत्रा:

हां, कृपया ऐसा करें। मैं भी इस पर जोर देना चाहता हूँ, कृपया केवल एक प्रश्न पूछें। और यदि आप दो प्रश्न पूछते हैं, तो मेरे पास यह विकल्प है कि मैं कौन सा प्रश्न का उत्तर दूंगा। इसलिए, कृपया बहुत सावधान रहें, आप कौन सा प्रश्न पूछना चाहते हैं। और यदि कोई प्रश्न बचे हैं, जो मुझे लगता है ऐसा होगा, तो हम वापस

आ सकते हैं। इसलिए, यह न सोचें कि आपका प्रश्न बिना उत्तर के रह जाएगा, बशर्ते यह एक अलग प्रश्न हो जो यहां मौजूद 26 प्रतिभागियों में से किसी ने नहीं पूछा हो। इसलिए, कृपया इस नियम का पालन करें और इसे संक्षिप्त रखें।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं CNBC TV18 से श्रीमती लता वेंकटेश से अनुरोध करूंगा कि कृपया पहला प्रश्न पूछें। लता, कृपया।

लता वेंकटेश, CNBC TV18:

बहुत बहुत धन्यवाद, श्री ब्रिज राज, गवर्नर और सभी। सर, बाजार ने आपके नीति वक्तव्य को उम्मीद से अधिक सौम्य पाया। और उनका तर्क था, यदि आप अपने मुद्रास्फीति अनुमानों को देखें, तो यह लगभग एक वर्ष के लिए 5% से अधिक है। इसका अर्थ है कि आपके लक्ष्य से 100 आधार अंक ऊपर, दिए गए लक्ष्य से बहुत ऊपर। इसके अलावा, वास्तविक दर, इसलिए, अगले छह महीने या इसके आसपास के अधिकांश समय के लिए ऋणात्मक हो जाती है। तो, क्या आप मुख्य मुद्रास्फीति पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं और जब आप घटाते हैं, तो आप टी-बिल को देख रहे हैं, यदि आप एक वर्ष आगे के टी-बिल लेते हैं और एक वर्ष आगे की मुख्य मुद्रास्फीति घटाते हैं, तभी आप लगभग 1.4% की वास्तविक दर के पास आते हैं। मेरा मतलब है, क्या आप ऋणात्मक वास्तविक दर या बहुत, बहुत कम वास्तविक दर के साथ समझौता करने जा रहे हैं?

संजय मल्होत्रा:

तो, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, हम न तो नरम रुख वाले हैं और न ही सख्त रुख वाले। हम महसूस करते हैं कि यह हमारी वर्तमान संवृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता और हमारे द्वारा स्वयं प्रक्षेपित संभावना के लिए उचित नीति दर है। बहुत अनिश्चितता है जो, निश्चित रूप से आगे आएगी।

ढांचा बहुत स्पष्ट है। मुझे नहीं लगता कि ढांचे के बारे में कोई भ्रम होना चाहिए। हमारा लक्ष्य हेडलाइन है, यह मुख्य या मुख्य बिना दबाव नहीं है। यह हेडलाइन मुद्रास्फीति है, जो हमें दिया गया लक्ष्य है और हम हेडलाइन मुद्रास्फीति के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। और यह हमारी प्रतिबद्धता होगी, यह हमारा प्रयास होगा कि मध्यम अवधि में हेडलाइन मुद्रास्फीति को लक्ष्य के अनुरूप लाया जाए, जैसा कि पहले भी उल्लेख किया गया था।

अब, हम मुख्य क्यों देखते हैं - और मुख्य इसलिए है क्योंकि हमें यह जानने की आवश्यकता है कि अंतर्निहित मुद्रास्फीति क्या है और हेडलाइन या अंतर्निहित मुद्रास्फीति आगे कैसे अभिसरण करेगी, क्योंकि भोजन और अब ईंधन के कारण, बाहरी झटकों के कारण, हेडलाइन मुद्रास्फीति बहुत अस्थिर हो सकती है। और इसलिए, जैसा कि मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उल्लेख किया था, कि यह अस्थिरता कुछ ऐसी नहीं है जिसे हम अपनी नीति रेपो दर में भी लाना चाहेंगे। इसलिए, यह मध्यम अवधि में है कि हम अपनी नीति का लक्ष्य रखते हैं -

मध्यम अवधि, हमारी हेडलाइन मुद्रास्फीति का लक्ष्य रखते हैं। और इसके अनुसार, हम आवश्यक कार्रवाई करेंगे, संभावना और संवृद्धि -मुद्रास्फीति गतिशीलता के आधार पर।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। हम इस तरफ आने से पहले अपने बाईं ओर से कुछ और प्रश्न लेंगे। मैं अब बिजनेस स्टैंडर्ड से मनोजित साहा से अनुरोध करूंगा कि वह अपना प्रश्न पूछें। मनोजित, कृपया।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

धन्यवाद, सर। मेरा प्रश्न FCNR(B) योजना पर है। क्या आपके पास एक विकल्प है कि यदि एक निश्चित राशि का प्रवाह आ रहा है, तो डेडलाइन से पहले योजना को समय से पहले ही बंद करने का? आपके मन में एक लक्ष्य हो सकता है। इसलिए, मैं यह पूछ रहा हूं क्योंकि इस योजना की लागत है क्योंकि आरबीआई इसे सब्सिडाइज़ कर रहा है। और एक दृष्टिकोण है कि स्थिति अब 2013 जितनी खराब नहीं है, जब भारत को कमजोर पांच में शामिल किया गया था, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि केवल 275 अरब डॉलर थी जबकि अब लगभग 700 अरब डॉलर हैं। इसलिए, वह चिंता है। तो, क्या आपके मन में कोई विकल्प है कि एक बार जमा राशि प्राप्त कर लें, तो इसे समय से पहले बंद कर दें?

संजय मल्होत्रा:

जैसा कि आपने उल्लेख किया है, हमारे पास मजबूत प्रवाह हैं। और हम आशा करते हैं कि आगे भी अच्छे, स्वस्थ प्रवाह मिलेंगे। अभी तक, योजना को समय से पहले बंद करने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हम आपको इसके बारे में अपडेट रखेंगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं अब ब्लूमबर्ग से अनूप रॉय से अनुरोध करूंगा कि वह अपना प्रश्न पूछें। अनूप, कृपया।

अनूप रॉय, ब्लूमबर्ग:

धन्यवाद, सर। सर, हमने देखा है कि FCNR(B) योजना द्वारा 40 अरब डॉलर जुटाए गए हैं और फिर भी, रुपया बहुत अधिक मजबूत नहीं हुआ है। मैं बस यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि वहां क्या हो रहा है। क्या यह इसलिए है कि आप अपनी फॉरवर्ड स्थिति का निष्कर्ष निकाल रहे हैं और डॉलर बाजार में नहीं आ रहा है? क्या आप कृपया हमें बता सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है?

संजय मल्होत्रा:

मुझे लगता है कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की अंतर्निहित मूलभूत बातें बहुत मजबूत हैं, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने जैसा तर्क दिया है, उसके अनुसार यह शायद नाममात्र या वास्तविक प्रभावी विनिमय दर के संदर्भ में अवमूल्यित हो सकता है। बहुत अनिश्चितता है। यह बहुत संभव है कि आगे जाकर जैसे तनाव और संघर्ष कम होते जाएंगे, रुपया आगे भी मजबूत हो सकता है। यह पिछले एक महीने या इसके आसपास से मजबूत हुआ है। यह 97 स्तर से अब लगभग 95 स्तर तक मजबूत हुआ है। इसलिए, यह मजबूत हुआ है।

और हमारी नीति हमेशा से यह रही है कि बाजार ही मूल्य स्तर और बैंड निर्धारित करते हैं। हम इसे नहीं करते हैं। हम केवल लक्ष्य रखते हैं - हम केवल तब हस्तक्षेप करते हैं जब अत्यधिक अस्थिरता होती है, जब विशेष दबाव बन रहे होते हैं। और यह हमारा प्रयास होगा कि रुपये के लिए पथ व्यवस्थित रहे, और कोई विघटनकारी गति न हो या कोई अपेक्षा न हो, आप जानते हैं, आत्म-पूर्ण अपेक्षाएं विनिमय दर में न बनें।

अनूप राय:

धन्यवाद।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं मनीकंट्रोल से हम्सिनी कार्तिक को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। हम्सिनी, कृपया।

हम्सिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:

धन्यवाद, सर। शुभ दोपहर। मेरा प्रश्न भी FCNR(B) से संबंधित है। मैं यह समझना चाहूंगी कि क्या आप कृपया हमें इस जमा प्रवाह के भौगोलिक वितरण के बारे में बता सकते हैं और क्या जमा प्रवाह ने आरबीआई के दृष्टिकोण से बीओपी प्रबंधन, तरलता और विदेशी मुद्रा के संदर्भ में सभी बॉक्स टिक किए हैं?

संजय मल्होत्रा:

हां, अभी तक, यह सभी बॉक्स टिक कर चुका है। आपने दो प्रश्न पूछे, लेकिन वे संबंधित हैं, इसलिए यह ठीक है।

हम्सिनी कार्तिक:

धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

और आपका दूसरा प्रश्न भौगोलिक क्षेत्रों पर है। हमारे पास नहीं है। हम भौगोलिक क्षेत्रों का संग्रह नहीं करते हैं। लेकिन प्रवाह, जैसा कि मैंने कहा, मजबूत रहे हैं। हमारे पास इन उपायों से पहले भी एक बहुत मजबूत और सहज बाहरी स्थिति थी। यह हमारी बाहरी स्थिति, जिसमें बीओपी भी शामिल है, को और मजबूत बनाता है।

हमिसनी कार्तिक:

धन्यवाद, सर।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं अब जी बिजनेस से एक्ता सूरी को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। एक्ता, कृपया।

एक्ता सूरी, जी बिजनेस:

सर, आज आपने अपनी नीति में एक वक्तव्य में उल्लेख किया कि बैंकों के मार्जिन पहले जैसे लाभदायक या अच्छे या बेहतर नहीं रहे हैं। तो, सर, क्या आरबीआई ने इसे ध्यान में रखा है, और क्या यही एक कारण है कि आपने बल्क जमा के लिए अलग-अलग दरों पर एक पेपर जारी किया? क्या यही एक कारण है? और क्या आरबीआई ट्रैक करेगा कि बैंक बल्क जमा के नाम पर कुछ पक्षों को विपणन खर्च या किसी अन्य तरीके से अतिरिक्त पैसा दे रहे हैं? क्या आरबीआई इसे ट्रैक करेगा? और इसी तरह, जब परिणाम आते हैं, बैंक अस्थायी रूप से फिक्स्ड डिपॉजिट लेकर बढ़ाया हुआ कासा दिखाते हैं। तो, आरबीआई इसका कैसे समाधान करेगा, सर?

संजय मल्होत्रा:

हमने पहले जारी की गई ब्याज दर दिशानिर्देश, वे NIMs के कारण नहीं थे, NIMs में गिरावट के कारण थे। जमा की अंतर्निहित लागत, जो अलग-अलग जमाकर्ताओं के लिए अलग हो सकती है, क्योंकि हमारे निदेश, विशेष रूप से एलसीआर के लिए, अलग हैं। इसलिए, इसे ध्यान में रखते हुए, हमने उन दिशानिर्देशों को जारी किया।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं अब ET Now Swadesh से अनुराग शाह को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। अनुराग, कृपया।

अनुराग शाह, ET Now Swadesh:

नमस्ते, सर। सर, आज आपने ऋण ब्याज दर गणना के बारे में एक बड़ी घोषणा की है। क्या यह एक बड़ी घोषणा है, जैसे कि आपने मिस सेल्लिंग के बारे में की थी, जो 1 जनवरी से लागू हो रही है, और जिसे अन्य विनियामकों से भी बहुत सराहना मिली? तो, लाखों-करोड़ों के ऋण लेने वाले सामान्य लोगों को इन ऋण ब्याज दर गणना नियमों से क्या राहत मिलेगी, ये नियम कब लागू होंगे, और आरबीआई कैसे दिशानिर्देश जारी करेगा ताकि लोगों को राहत मिले?

संजय मल्होत्रा:

इन ब्याज दर नियमों का मुख्य कारण यह है कि हमारे विभिन्न विनियमित संस्थाओं द्वारा अलग-अलग निर्देश जारी किए गए थे। इसलिए, उन्हें तर्कसंगत और मानकीकृत करने के लिए, हमने ये नियम जारी किए हैं। और इसके माध्यम से, पारदर्शिता भी बढ़ेगी क्योंकि सभी को पता चलेगा कि ब्याज दरें क्या हैं और वे कैसे निर्धारित की जाती हैं। इसलिए, मुख्य रूप से यह एक तर्कसंगतीकरण प्रयास है, जो उपभोक्ता सुरक्षा को और बढ़ाएगा।

अनुराग शाह:

तो, लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि ईएमआई बदल जाएगा? ईएमआई वही रहेगा, लेकिन आप अपने ब्याज और मूलधन को एक उचित, पारदर्शी तरीके से समझेंगे।

लता वेंकटेश:

सर, क्या आप कृपया दोहरा सकते हैं? क्योंकि यह मेरा दूसरा प्रश्न भी था। बाजार बहुत भ्रमित है कि 'सभी विनियमित संस्थाओं' से क्या मतलब है? क्या NBFCs को EBLR घोषित करना होगा? यह सभी भ्रम हैं।

मनोजित साहा:

क्या NBFCs के पास बाहरी बेंचमार्क होना चाहिए?

संजय मल्होत्रा:

ये सभी विवरण हमारे द्वारा जारी किए जाने वाले मसौदा दिशानिर्देशों में होंगे। इसलिए, कृपया उन दिशानिर्देशों का इंतजार करें। सभी विवरण वहां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, यह कोई बड़ा बदलाव नहीं है। NBFCs और उन्हें EBLR पर लाने के संदर्भ में आप जिस आवश्यकता का उल्लेख कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं है। केवल एक तर्कसंगतीकरण है। शायद डीजी शिरीश आगे स्पष्ट कर सकते हैं।

शिरीश सी. मुर्मू:

आप सही कह रहे हैं, सर। आपको परिपत्र आने का इंतजार करना होगा। मैं जो बता सकता हूँ, वह है कि कोई बड़ा बदलाव नहीं है। और जोर पारदर्शिता पर है और यह मूल रूप से आचरण से संबंधित है। इसलिए, वास्तविक भाग पर नजर न डालें, लेकिन फिर भी, परिपत्र का इंतजार करें, यह जल्द ही आएगा।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। हम अब दाईं ओर से कुछ प्रश्न लेंगे। मैं इकोनॉमिक टाइम्स से संगीता मेहता को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। संगीता, कृपया।

संगीता मेहता, इकोनॉमिक टाइम्स:

धन्यवाद। सर, आपके नीति वक्तव्य में, आपने कहा है कि नीति दरों का प्रसार कम हो गया है। और अब स्वैप विंडो खुलने के साथ, हम तरलता में वृद्धि की उम्मीद करते हैं, और यह बढ़ चुकी है, और आगे भी बढ़ सकती है। क्या आप उम्मीद करते हैं कि बैंक तरलता के लाभों को ग्राहकों तक पहुंचाएं, क्योंकि बैंक पहले से ही NIMs में सुधार और ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं? इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है।

संजय मल्होत्रा:

तरलता स्पष्ट रूप से सभी की मदद करेगी। यह आवश्यक था, लेकिन मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि तरलता केवल बहुत अल्पावधि के लिए ही अधिशेष में हो सकती है। यह लगभग सितंबर या उसके आसपास दूसरी तिमाही में शिखर पर पहुंच सकती है। और आगे बढ़ते हुए, यह हमारी अर्थव्यवस्था की सामान्य आवश्यकताओं के कारण अवशोषित हो जानी चाहिए, जैसे कि प्रचालन में मुद्रा की वृद्धि, जमा वृद्धि के कारण आरक्षित निधि आवश्यकताओं में वृद्धि। हमारे पास कुछ फॉरवर्ड भी हैं जो परिपक्व हो रहे हैं। इसलिए, समग्र रूप से, आप अवश्य जानते हैं, यह मदद करेगा, लेकिन यह असामान्य रूप से उच्च तरलता नहीं है।

संगीता मेहता:

क्या यह उत्तर देता है, क्या आप आशा करेंगे कि बैंकों के पास अभी भी कुछ पास ऑन होगा...?

संजय मल्होत्रा:

जैसा कि मैंने उल्लेख किया, यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए, इससे केवल बहुत हद तक मदद मिलेगी। यह बहुत अल्पावधि के लिए असामान्य या महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा मतलब है, यह वह तरलता है जो हम अन्यथा, हर वर्ष, ओएमओ और अन्य साधनों, स्वैप के माध्यम से, इस तरह की तरलता प्रदान करते हैं। अब, इसमें से बहुत कुछ, बिल्कुल, एफसीएनआर (बी) जमा की मात्रा पर निर्भर करेगा, लेकिन यह अधिकांशतः मध्यम अवधि में अवशोषित हो जाना चाहिए।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं थॉमसन रॉयटर्स से जसप्रीत कलरा को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। जसप्रीत, कृपया।

जसप्रीत कलरा, थॉमसन रॉयटर्स:

धन्यवाद, सर। गवर्नर, मेरा प्रश्न बैंकों में उत्तराधिकार योजना से संबंधित है। ऐसे मामले रहे हैं जहां बैंकों ने शीर्ष नेतृत्व के लिए छह महीने के नवीनीकरण चक्र से अधिक समय लिया है, कुछ अन्य स्थानों पर, सीईओ एक कार्यकाल के भीतर ही चले गए हैं। भारत के लिए बड़े बैंकों को वैश्विक पहुंच वाला बनाने के लक्ष्य को देखते हुए, विश्लेषकों ने यह भी बताया है कि बैंकों में शीर्ष प्रतिभा के लिए पारिश्रमिक आदि पर कड़ा नियंत्रण बैंकों द्वारा आकर्षित की जाने वाली प्रतिभा पर सीमित प्रभाव डाल सकता है। क्या आपको लगता है कि अभी लागू कुछ नियमों की समीक्षा करने और भविष्य में उनमें से कुछ में ढील देने की गुंजाइश है?

संजय मल्होत्रा:

अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

जसप्रीत कलरा:

क्या आपको बड़े बैंकों के लक्ष्य को देखते हुए आवश्यकता नहीं लगती?

संजय मल्होत्रा:

हमारी स्पष्ट रूप से आवश्यकता है - हम सभी स्पष्ट रूप से अधिक और अधिक बैंक चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने उल्लेख किया, यह बाधा बन रहा है या नहीं, इस पर हमने अभी तक विचार नहीं किया है, और इस संबंध में कोई लंबित प्रस्ताव नहीं है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं एनडीटीवी प्रॉफिट से पीयूष शुक्ला को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। पीयूष, कृपया।

पीयूष शुक्ला, एनडीटीवी प्रॉफिट:

गुड अफ्टरनून, गवर्नर, डीजी। धन्यवाद, ब्रिज सर। सर, कल सरकार ने भुगतान अधिनियम में कुछ संशोधन किए हैं। अब, चर्चा है कि सरकार कुछ लेनदेन पर एमडीआर लगा सकती है, चाहे वह ₹2,000 से अधिक हो, या यह बड़े खुदरा विक्रेताओं पर लगा सकती है।

आपने पहले उल्लेख किया था कि इस सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपयोगिता की लागत किसी को वहन करनी होगी। मैं आरबीआई से समझना चाहता हूं, क्या हम लेनदेन के आकार पर विचार करेंगे? क्या हम कुछ विशिष्ट खुदरा विक्रेताओं को लक्षित करेंगे? आगे की कार्यनीति क्या है, यदि आप इस संबंध में कुछ दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं, सर? और पिछली बार, सर, आपने कहा था कि एनबीएफसी की ऊपरी स्तर की सूची बहुत जल्द आएगी। तो, यह कितनी जल्दी आएगी, सर?

संजय मल्होत्रा:

तो, मैं आपका पहला प्रश्न उत्तर दूंगा कि यह अभी बहुत जल्दबाजी है। सरकार अभी भी संशोधन कर रही है। लागत किसी को चुकानी होगी। मेरा मतलब है हम सभी चाहते हैं कि यह सार्वजनिक बुनियादी ढांचा आगे बढ़े, अधिक कुशल बने, आदि। हम ऐसा करते रहेंगे। यह अभी हमारा प्राथमिक ध्येय है। इंतज़ार करके देखते हैं कि इस पर आगे क्या विकास होता है। मेरे पास इसमें और कुछ जोड़ने के लिए नहीं है।

पीयूष शुक्ला:

हां, क्या उपयोगकर्ता को शुल्क लगाया जाएगा? क्योंकि यदि आप व्यापारी पर शुल्क लगाते हैं, तो अंततः यह ग्राहक पर आ जाता है। इसलिए, लक्ष्य 800 मिलियन लेनदेन प्रति दिन या उसके आसपास है।

संजय मल्होत्रा:

इंतज़ार करते हैं। यह अभी बहुत जल्दबाजी है। लेकिन कृपया ध्यान रखें कि अंततः यह किसी न किसी रूप में उपभोक्ता ही भुगतान कर रहा है। इसलिए, यह वही उपभोक्ता नहीं हो सकता है। यह, सामान्य अर्थव्यवस्था हो सकता है, और आप इसे सीधे नहीं देख पाते हैं। लेकिन पहले से ही यह है, आपके प्रश्न का आंशिक उत्तर देने के लिए, कि क्या यह किसी तरह से पास हो रहा है, यह पहले से ही पास हो रहा है। यह सीधे उपयोगकर्ता भुगतान सिद्धांत पर नहीं हो सकता है, लेकिन कोई न कोई लागत भुगतान कर रहा है। यही मेरा मतलब था। किसी को तो लागत भुगतान करना होगा। मैंने पहले भी यह कहा था, और अभी भी मैं ऐसा कह रहा हूं। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम निवेश जारी रखें, और हम तरीके ढूंढते रहें, चाहे वह एमडीआर या अन्य चीजों के माध्यम से हो। मुझे लगता है कि ये ब्योरे के मामले हैं। आइए इंतज़ार करते हैं और देखते हैं कि आगे की स्थिति कैसे विकसित होती है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं ईटी नाउ से अंकुर मिश्रा को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। अंकुर, कृपया।

अंकुर मिश्रा, ईटी नाउ:

धन्यवाद, ब्रिज सर, और गुड अफ्टरनून, गवर्नर। सबसे पहले, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कच्चे तेल और रुपये पर अनुमान क्या है? कृपया इसे प्रश्न के रूप में न लें। पूछने के लिए, मैं जीडीपी के संबंध में आपकी समझ जानना चाहता हूँ। पिछली से पिछली नीति में, बिल्कुल, वित्त वर्ष 27 का अनुमान 6.9% था, फिर यह 6.6% हो गया, और अब हम 6.7% पर हैं। दिए गए पहले तिमाही में आप कह रहे हैं कि 7% वृद्धि संभव है। क्या वित्त वर्ष 27 के लिए समग्र 7% वृद्धि की संभावना है, जो इस तथ्य को देखते हुए संभव है कि पिछले समय में आए डेटा भी अनुमान से बेहतर रहे हैं?

संजय मल्होत्रा:

हमने जो 6.7% वृद्धि का अनुमान लगाया है - जो संभावना हमने दिया है वह एक अनुमान है, और हमने यह भी उल्लेख किया है कि दोनों ओर जोखिम समान रूप से संतुलित हैं। हम एक फैन चार्ट भी देते हैं जो सापेक्ष संभावना वितरण दिखाता है। इसलिए, यदि आप फैन चार्ट को देखें, तो यह सुझाव देगा कि वृद्धि की संभावना है, जो आपके प्रश्न का उत्तर देता है, वृद्धि 7% या उससे अधिक हो सकती है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं मिनट से शयान घोष को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। शयान, कृपया।

शयान घोष, मिनट:

गवर्नर, मैं समझना चाहता था, अप्रैल में, आरबीआई ने बैंकों से आईए विषयक साइबर सुरक्षा आघात सहनीयता पर बोर्ड-अनुमोदित नीति आरबीआई को सौंपने को कहा था। और दो महीनों के भीतर, हमने एक बड़े बैंक को एक साइबर घटना का सामना करते देखा जहां बहुत सारा ग्राहक डेटा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। जब बैंक इन दिशानिर्देशों का पालन नहीं करते हैं या इन हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं होते हैं, तो बैंकिंग क्षेत्र में ऐसी घटनाओं की लागत होगी?

संजय मल्होत्रा:

हमारे प्रमुख बैंकों और बड़े विनियमित संस्थानों की आईटी प्रणाली काफी मजबूत, दृढ़ हैं। उन्होंने सुनिश्चित करने के लिए जांच और संतुलन लगाए हैं कि वे सुरक्षित हैं। हमारे पास न केवल दिशानिर्देश और विनियम हैं, बल्कि हमारे पास एक निगरानी भी है जो बहुत नियमित रूप से की जाती है। जब भी कोई कमियां या कमजोरियां बताई जाती हैं, तो प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाए जाते हैं। उनका अनुसरण किया जाता है, उनकी निगरानी की जाती है, और उनका अनुसरण किया जाता है ताकि प्रणाली लगातार नए खतरों और कमजोरियों के साथ आईटी क्षेत्र में नए विकास के साथ आगे बढ़ते रहें। साथ ही, हमारे बैंक और विनियमित संस्थान भी अपने आप को और सुरक्षित और आघात सह बनाने के लिए तैयार रहते हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं मीडिया के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया केवल एक प्रश्न पूछें, जैसा कि पहले सूचित किया गया था। मैं हिंदू बिजनेस लाइन के के. राम कुमार से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रश्न पूछें। राम कुमार, कृपया।

के. राम कुमार, हिंदू बिजनेस लाइन:

ऋण और जमा वृद्धि के बीच एक अंतर रहा है, जिसमें ऋण वृद्धि जमा वृद्धि से वास्तव में बहुत अधिक संख्या से आगे निकल गई है। तो, मैं यह समझना चाहता था कि क्या इससे ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जहां ऋण दरें बढ़ेंगी, जमा दरें बढ़ेंगी? और मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मौद्रिक नीति प्रसार पूर्ण हो गया है?

संजय मल्होत्रा:

तो, मैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। मौद्रिक नीति प्रसार लगभग 80 आधार अंक है, यह कम हो गया है। यह उधर की ओर से लगभग 90 आधार अंक था, इसलिए मैं कहूंगा कि यह अधिकांशतः पूर्ण है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब हम बाईं ओर से शेष प्रश्न लेंगे। मैं दक्कन क्रॉनिकल की फलकनाज सैयद से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रश्न पूछें। फलकनाज, कृपया।

फलकनाज सैयद, दक्कन क्रॉनिकल:

सर, रिपोर्टों के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक के पास लगभग ₹800 करोड़ की धनराशि अवरुद्ध है। उनमें से आधा अवरुद्ध है...

संजय मल्होत्रा:

विशिष्ट संस्थाओं के बारे में, हम प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। इसलिए, यदि आप कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। हम किसी विशिष्ट संस्था की बातें नहीं करते हैं - क्या यह प्रश्न विशिष्ट संस्था से संबंधित है या किसी से संबंधित सामान्य प्रश्न है ...

फलकनाज सैयद:

सामान्य, जैसे कि कितनी जमा राशि का दावा किया गया है, कितनी...

संजय मल्होत्रा:

नहीं, हम किसी विशिष्ट विनियमित संस्था के विशिष्ट विवरणों में नहीं जाते हैं।

फलकनाज सैयद:

ठीक है। और मोबाइल के मामले में डिफॉल्ट होने पर ऋणदाताओं द्वारा मोबाइल फोन लॉक किए जा सकते हैं, इसके लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी होने वाले हैं। तो, मसौदा दिशानिर्देश थे। अब, अंतिम दिशानिर्देशों में क्या बदलाव किए जाएंगे, और वे अंतिम दिशानिर्देश कब जारी होंगे? क्या यह स्थिति बनी रहेगी जहां ऋणदाताओं को फोन दूरस्थ रूप से लॉक करने की अनुमति होगी?

संजय मल्होत्रा:

हम अभी भी दिशानिर्देशों का विश्लेषण कर रहे हैं, और जल्द ही हम उन्हें अंतिम रूप देने में सक्षम होंगे। और मैंने अभी तक आई टिप्पणियों को नहीं देखा है। जैसा कि आपने कहा, हमने प्रस्तावित किया था कि विनियमित संस्थाओं को पर्याप्त सुरक्षा उपायों, नोटिस - अग्रिम नोटिस सहित, उनके निजी डेटा को सुरक्षित रखने, इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग न करने आदि के साथ चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधित करने की अनुमति दी जाए। हम सभी टिप्पणियों की जांच करेंगे और जल्द ही हम संशोधित दिशानिर्देश जारी करेंगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं फाइनेंशियल टाइम्स के कृष्ण कौशिक से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रश्न पूछें। कृष्ण, कृपया।

कृष्ण कौशिक, फाइनेंशियल टाइम्स:

नमस्कार, शुभ दोपहर, सर। तो, FCNR (B) पर वापस, मैं बस यह पूछना चाहता हूँ कि पहले जो मजबूत मोबिलाइज़ेशन होता था, वो बैक-एंडेड होता था, और इस बार, यह काफी अच्छा रहा है, पहले से ही 36 अरब डॉलर। तो, क्या यह उससे अधिक था जो नीति घोषित करने के समय उम्मीद की जा रही थी, और आप सितंबर के अंत तक इसे कितना पहुंचने की उम्मीद करते हैं?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, हमारे मन में कोई लक्ष्य नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है, धन प्रवाह मजबूत रहे हैं, और हम आगे भी अधिक स्वस्थ अंतर्वाह की उम्मीद करते हैं। हमारे मन में कोई संख्या नहीं है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं दि हिंदू के ललातेंदु मिश्रा से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रश्न पूछें। ललातेंदु, कृपया।

ललातेंदु मिश्रा, दि हिंदू:

शुभ दोपहर, सर। वैश्विक झटके कोविड की शुरुआत के बाद से बहुत बार हो रहे हैं, और पश्चिम एशिया संघर्ष के अंत के कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इन परिस्थितियों में, आप देश की जनता को क्या विश्वास देते हैं, और हम सभी को किस बात के बारे में चिंतित होना चाहिए? धन्यवाद, सर।

संजय मल्होत्रा:

मुझे लगता है कि विश्वास इस तरह से आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, हम सभी मिलकर, संस्थाओं सहित, इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, चाहे वह कोविड हो, चाहे यूक्रेन युद्ध हो, या चाहे यह वर्तमान झटका हो जिसे हमने देखा। हम बाहर आ गए हैं - हमने न केवल इन चुनौतियों का सामना किया, बल्कि हम मजबूत होकर बाहर आए। और यह विशेष घटना या झटका हमारे लिए अपनी आघात सहनीयता को और बढ़ाने का एक अवसर के रूप में देखा जा रहा है।

हमारी समष्टि आर्थिक मूलभूत स्थिति, दूसरी बात, बहुत मजबूत है। वृद्धि आघात-सह है। मुद्रास्फीति, हालांकि हेडलाइन बढ़ रहा है, लेकिन अंतर्निहित मुद्रास्फीति के दबाव कम हैं, जबकि हम देखते हैं, यह मूल मुद्रास्फीति के साथ संरेखित हो रहा है। आपके बैंक, आपके निगम, आपके घरेलू क्षेत्र, उनके पास अच्छे, स्वस्थ बैलेंस शीट हैं।

सरकार सुधारों पर ध्यान केंद्रित करती रहती है, वित्तीय संकलन के मार्ग पर आगे बढ़ती रहती है। हमारे नीति ढांचे मजबूत हैं, संस्थाएं मजबूत हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यही वह है जो हमें विश्वास देता है कि, जो भी हो, हम प्रत्येक घटना से मजबूत होकर बाहर आएंगे। चिंता करने की कोई बात नहीं है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं बिजनेस टुडे के नचिकेत केलकर से अनुरोध करूंगा कि वे अपना प्रश्न पूछें। नचिकेत, कृपया।

नचिकेत केलकर, बिजनेस टुडे:

शुभ दोपहर, गवर्नर। बस एक प्रश्न, सावधि जमा और दरों की एकरूपता पर आए परिपत्र पर। उस परिपत्र को किसने प्रेरित किया? क्या आपने ऐसे मामले पाए जहां अलग-अलग मूल्य निर्धारण ऑफर किए जा रहे थे? और क्या यह जमा जुटाने को प्रभावित करेगा क्योंकि बैंकों को वैसे भी जमा के मामले में संघर्ष करना पड़ रहा है, विशेष रूप से छोटे वित्त बैंक? क्या यह एक गति बाधा नहीं होगी?

संजय मल्होत्रा:

जमा पर?

नचिकेत केलकर:

हां।

संजय मल्होत्रा:

देखिए, कुछ पहलुओं में स्पष्टता की कमी थी, इसलिए, मुख्य रूप से, हमने मानकीकृत और स्पष्ट किया है कि जमा दरों को पारदर्शी तरीके से कैसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार कोई बड़ा बदलाव नहीं है, जब तक कि आप कुछ बिंदुओं पर जोर देना चाहते हो जहां हमने स्पष्टता दी है। मेरा मतलब है, यह सब पारदर्शिता के बारे में है।

हमने उनसे कहा है कि वे पहले से ही, जो कुछ बैंकों के लिए पहले से मौजूद था, और बैंक पहले से ही ऐसा कर रहे थे, लेकिन उन्हें पहले से कैसे सूचित किया जाए। इसलिए, हमने कहा है कि आप अपनी वेबसाइट के माध्यम से उन्हें जमा के बारे में पहले से सूचित करें। इसी तरह, बल्क जमा के लिए समय का मानकीकरण नहीं था। इसलिए, हमने कहा है कि हमने उन्हें बल्क जमा के लिए सुबह 10:00 बजे तक की छूट दी है। तो, यह ऐसी चीजें हैं। आप कुछ जोड़ना चाहेंगे, शिरीष?

शिरीष सी. मुर्मू:

नहीं, मैं केवल आशय जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि विवरण परिपत्र में हैं। वास्तव में, पारदर्शिता और सबके लिए समान अवसर - ये हमारी मुख्य प्राथमिकताएँ हैं। और हमने इन परिपत्रों के माध्यम से इन्हें प्राप्त करने का प्रयास किया है। इसीलिए हमने समय को भी मानकीकृत किया है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया से मनीष सुवर्णा को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। मनीष, कृपया।

मनीष सुवर्णा, पीटीआई:

शुभ दोपहर, गवर्नर सर। मुझे सिर्फ यह समझने की आवश्यकता है, क्या आप उम्मीद करते हैं कि सरकार के उपाय ग्रामीण मांग को एल नीनो के प्रभाव से बचाने के लिए पर्याप्त होंगे? और दूसरा, सर, क्या वर्तमान विकास कहानी अब अधिकांशतः शहरी उपभोग पर निर्भर हो रही है, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि निजी उपभोग मजबूत बना हुआ है और ग्रामीण मांग में कमजोरी है?

संजय मल्होत्रा:

मुझे लगता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र, ने अधिक आघात सहनीयता दिखाई है। मानसून अभी भी विद्यमान है, एल नीनो की स्थिति हुई है, लेकिन फिर आपके पास दूसरा विपरीत ध्रुव है,

जो शायद एल नीनो के कुछ प्रभावों को निरस्त कर सकता है। यह अभी भी विकसित हो रहा है, लेकिन यह बहुत लचीला रहा है क्योंकि विभिन्न उपायों के कारण, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि सरकार ने उठाए हैं। सहायक गतिविधियां, वे - हमने देखा है कि यदि एक वर्ष में कृषि अच्छा नहीं चल रहा है, तो सहायक क्षेत्र बहुत अच्छा चल रहा है। परिवार अपनी गतिविधियों को स्वयं समायोजित करने में सक्षम हैं ताकि आय उत्पन्न कर सकें और आय में हुए नुकसान को कम कर सकें जैसा कि हमने देखा है। सिंचाई में सुधार हुआ है। सरकार ने कई उपाय उठाए हैं। मैडम [DG(PG)], क्या आप यहां कुछ जोड़ना चाहेंगी?

डॉ. पूनम गुप्ता:

मैं जोड़ सकती हूं, और मैं लगभग वही दोहराऊंगी जो अभी सर ने कहा। अब, हमने देखा है कि समग्र अर्थव्यवस्था बहुत आघात-सह्य हो गई है, और यह आघात सहनीयता विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है, विशेष रूप से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। और यदि आप पिछले, मान लीजिए, 15 वर्षों के आंकड़ों को देखें, तो आप देखेंगे कि आघात सहनीयता कई तरीकों से प्रकट होता है।

मैं सिर्फ कुछ बिंदुओं की ओर इशारा करूंगी। एक, जैसा कि सर ने कहा, कृषि क्षेत्र है और एक सहायक क्षेत्र है। दोनों क्षेत्र बहुत अच्छे हो गए हैं, और वे एक दूसरे को पूरक बनाते हैं, विशेष रूप से यदि हम देखें कि एक वर्ष में कृषि अच्छा नहीं चल रहा है, तो सहायक क्षेत्र बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरा, यदि आप सरकार के कुछ उपायों को देखें, तो अब सिंचित क्षेत्र का हिस्सा बहुत बड़ा है, और यह एक दीर्घकालिक वृद्धि है, जिसका अर्थ है कि हालांकि वर्षा की कमी और अनिश्चितताएं मायने रखती हैं, लेकिन वे पहले की तुलना में कम मायने रखती हैं। यदि आप कृषि क्षेत्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले इनपुट्स को देखें, चाहे वह क्षेत्र को ऋण के माध्यम से हो या कृषि यांत्रिकीकरण, तो यह बहुत अच्छी तरह से सुधरा है। फसल की किस्म और बीज की किस्म में सुधार हुआ है। इसलिए, सभी मिलाकर, ये सभी उपाय एक अच्छी तरह से चल रही ग्रामीण अर्थव्यवस्था और एक बहुत आघात-सह्य कृषि क्षेत्र की ओर इंगित करते हैं।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर और धन्यवाद, मैडम। मैं आईएनएस से सौरभ पांडेय को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। सौरभ कृपया।

सौरभ पांडेय, आईएनएस:

शुभ दोपहर, गवर्नर सर। जैसा कि हमने देखा है, आपको हाल ही में पॉलिमर नोट्स के लिए मंजूरी मिली है। तो, इसकी स्थिति क्या है, और कब तक हम इसे अस्तित्व में आते देख सकते हैं, सर?

संजय मल्होत्रा:

तो, देखिए, यह पॉलिमर चीज, मूल रूप से दो उद्देश्यों के लिए है। एक यह है कि यह टिकाऊपन और जीवनकाल को बढ़ाता है, विशेष रूप से आपके निम्न मूल्य वाले नोट्स के लिए जहां गति अधिक है, और इसलिए, जीवनकाल कम है। ये नोट विभिन्न देशों में 30 से अधिक वर्षों से परिचालन में हैं, और यह पाया गया है कि जीवनकाल बहुत अधिक है, कागज की सबस्ट्रेट की तुलना में 3x से 4x। और फिर यह हमारी क्षमता को भी बढ़ाता है क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, यह दूसरा उद्देश्य है, यह हमारी क्षमता को बढ़ाता है क्योंकि अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं बढ़ती हैं। इसलिए, इन उद्देश्यों के साथ हम इसे लेकर आए हैं। यह अभी भी एक प्रारंभिक स्तर पर है। हम परीक्षण करेंगे, जांच करेंगे कि वे भारतीय परिस्थितियों, जलवायु और अन्य बुनियादी ढांचे में कैसे प्रदर्शन करते हैं जो हमने स्थापित किए हैं। और उसके बाद ही हम देखेंगे कि क्या इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है या बदलाव के साथ। हम लक्ष्य रख रहे हैं कि यदि सब कुछ योजना के अनुसार चलता है, तो वे अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में परिचलन में होंगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं मीडिया व्यक्तियों से फिर से अनुरोध करूंगा कि कृपया केवल एक प्रश्न पूछें। आगे बढ़ते हुए, मैं इंडियन एक्सप्रेस से आकाश मंडल को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। आकाश, कृपया।

आकाश मंडल, इंडियन एक्सप्रेस:

शुभ दोपहर, गवर्नर, डीजी। मेरा प्रश्न मूल मुद्रास्फीति से संबंधित है। आपने अपने नीति वक्तव्य में कहा था कि बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति वित्तीय वर्ष के अंत तक मूल मुद्रास्फीति के साथ संरेखित हो जाएगी। लेकिन आपने यह भी उल्लेख किया था कि अभी तक मूल्य दबाव के सामान्यीकरण के कुछ संकेत हैं। तो, आगे बढ़ते हुए, आप किन कारकों को देखते हैं जो अगले कुछ महीनों में बहुमूल्य धातुओं को छोड़कर मूल मुद्रास्फीति को वर्तमान 2.5% से 4%, 4.3% तक बढ़ा सकते हैं?

संजय मल्होत्रा:

हां, तो यह विभिन्न कारणों से है कि मूल बढ़ रहा है, आप जानते हैं। मेरा मतलब है, यह 2.1 से 2.5 जैसे स्तर है, मूल अंतर्निहित मुद्रास्फीति – मूल दबाव को छोड़कर, और यह बढ़ रहा है, है ना? तो, सिर्फ मूल नहीं, बल्कि अंतर्निहित दबाव भी। तो, जो भी हो, अनुकूल मुद्रास्फीति जिसमें हम थे, स्पष्ट रूप से, आगे बढ़ते हुए, वह नहीं है। और इसलिए, हम उसके लिए नजर रख रहे हैं। और यदि उसके कारण नीति दरों को पुनर्परिकलित करने की आवश्यकता है, तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। सर, अब हम इस तरफ से शेष प्रश्न लेंगे। मैं द टाइम्स ऑफ इंडिया से मयूर शेटी को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। मयूर, कृपया।

मयूर शेटी, द टाइम्स ऑफ इंडिया:

धन्यवाद, सर। गवर्नर, मेरा प्रश्न FCNR (B) संग्रह के आरबीआई के बैलेंस शीट पर प्रभाव पर था। आप आरबीआई को मिलने वाले स्वैप स्थितियों के साथ कैसे निपटने की योजना बना रहे हैं?

संजय मल्होत्रा:

देखिए, हम स्वैप करते रहते हैं, है ना? हम स्वैप करते हैं। हम विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री करते हैं, और जो भी हमारी आरक्षित निधियाँ हैं, उसके परिणामस्वरूप, एक समिति है, एक उच्च स्तरीय समिति है, सरकार के सदस्य भी हैं जो नियमित रूप से उन बैठकों में भाग लेते हैं, और हम तय करते हैं कि हम आरक्षित निधियों को कैसे प्रबंधित करेंगे।

तीन सिद्धांतों के आधार पर, मैंने एक साक्षात्कार में उल्लेख किया था, पहला सुरक्षा है, दूसरा तरलता है, और तीसरा विवरणियाँ हैं। तो, सुरक्षा, तरलता और विवरणियाँ। इसलिए, उसके आधार पर लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, यह तरलता नहीं है जो यह इंजेक्ट करेगा, वह कुछ समय के लिए है। बैलेंस शीट बढ़ रही है, आप जानते हैं, अधिक या कम सामान्य गति से, जब तक आपके पास अप्रत्याशित जमा की बाढ़ नहीं है, जो हम नहीं (उम्मीद) करते हैं। यह प्रबंधनीय है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं इनफॉर्मिस्ट मीडिया से आर्यन खन्ना को अपना प्रश्न पूछने के लिए अनुरोध करूंगा। आर्यन, कृपया।

आर्यन खन्ना, इनफॉर्मिस्ट मीडिया:

धन्यवाद, सर। शुभ दोपहर। गवर्नर, बस, तरलता के संदर्भ में उसी विचार धारा पर आगे बढ़ते हुए। अभी आपने कहा है कि, आप उम्मीद नहीं करते कि तरलता प्रणाली में बहुत लंबे समय तक रहेगी, और इसे अर्थव्यवस्था द्वारा उपयोग किया जाएगा। अब, ऋण वृद्धि पहले से ही 18% पर है, यह अंतिम बार एमपीसी की बैठक के बाद बढ़ी है। क्या आरबीआई का अब का इरादा मांग या मांग-जनित मुद्रास्फीति बढ़ाना है, क्या यह इसलिए है क्योंकि मूल मुद्रास्फीति शायद 4% से कम है? तो, क्या अब आरबीआई का रुख यह है कि आप त्योहार के महीनों में मांग बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि तरलता अर्थव्यवस्था द्वारा उपयोग की जाएगी?

संजय मल्होत्रा:

हमारे पास मौजूदा नीति दर - तो, दो बातें, मैं कहूंगा। एक, तरलता, हम इसे इस तरह प्रबंधित करने की कोशिश करते हैं कि हमारा परिचालन लक्ष्य, जो WACR है, नीति रेपो दर के साथ संरेखित हो। तो, जो तरलता हम देंगे, वह नीति रेपो दर पर निर्भर करेगी। और नीति रेपो दर क्या होगी, वह संवृद्धि और मुद्रास्फीति गतिशीलता द्वारा निर्धारित होगी, जहां आपकी मांग भी आती है। इसलिए, यदि कोई शिथिलता है, जो है, जो हम संवृद्धि के संभावित स्तर से नीचे होने के साथ पाते हैं, तो स्पष्ट रूप से, उस सीमा तक, यह मांग में मदद करेगा।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। अब मैं दूरदर्शन की श्यामा मिश्रा से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करूंगा। श्यामा, कृपया।

श्यामा मिश्रा, दूरदर्शन:

नमस्कार, सर। सर, इस उच्च हेडलाइन मुद्रास्फीति के बावजूद, रुख की स्थिति अपरिवर्तित रही है। कौन से विशिष्ट संकेतक या गतिविधियां आरबीआई को इस स्थिति को बदलने या फिर से विचार करने के लिए प्रेरित करेंगे?

संजय मल्होत्रा:

स्पष्ट रूप से, यह संवृद्धि -मुद्रास्फीति गतिशीलता में परिवर्तन है। यदि बहुत अधिक मुद्रास्फीति है, जिसके लिए हमें दरें बढ़ानी हों, या दूसरी ओर, यदि संवृद्धि बहुत कम है, मुद्रास्फीति - प्राथमिक उद्देश्य, बिल्कुल, मुद्रास्फीति है। जब मैं यह कहता हूँ, तो मैं यह ध्यान में रखूंगा कि प्राथमिक उद्देश्य मूल्य स्थिरता है और इसलिए, यदि मुद्रास्फीति लक्ष्य से अधिक बढ़ रही है, लक्ष्य से संरेखित नहीं है, लंबे समय तक लगातार, जिसके लिए मैं कहूंगा, बड़ी दर कटौती की आवश्यकता है, तो यह पूरा होगा - और जब आप निश्चित हैं कि, आप ऐसी स्थिति में दरें बढ़ाने या बदलने जा रहे हैं, तो आप अपनी नीति बदल देंगे। यदि आप अनिश्चित हैं या यदि आप उम्मीद करते हैं कि नीति दरों में बहुत अधिक परिवर्तन नहीं होगा, तो आप स्थिति नहीं बदल सकते, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, और आप अभी भी डेटा-निर्भर रह सकते हैं, और आप दरों में परिवर्तन करने का निर्णय ले सकते हैं।

श्यामा मिश्रा:

लेकिन सर, यह पहले से ही उच्च स्तर पर है, और हम भविष्य के अनुमानों को भी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो, क्या हम आने वाले महीनों में परिवर्तन देखेंगे?

संजय मल्होत्रा:

देखते हैं कि आने वाले महीनों में क्या परिवर्तन होता है। हम डेटा-निर्भर रहेंगे। हम अपने प्राथमिक उद्देश्य, मूल्य स्थिरता बनाए रखने और मध्यम अवधि में 4% हेडलाइन मुद्रास्फीति के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित रखेंगे। और इसलिए, यह मुद्रास्फीति पथ पर निर्भर करेगा। जैसा कि हमने कहा है, हम देखते हैं कि यह घट रहा है, यह कहाँ तक घट रहा है, यह कितनी तेजी से घट रहा है, यह महत्वपूर्ण है। और यही वह है जिसे हमने बहुत स्पष्ट रूप से बताया है कि हम विशेष रूप से मुद्रास्फीति - मुद्रास्फीति पथ, इसकी रचना, जहाँ यह समाप्त होती है, इन सभी बातों पर हमारे संकल्प में ध्यान दे रहे हैं। और यह - और बहुत सारी अनिश्चितताएँ हैं, जैसा कि हमने कहा है, और इसलिए हम नीति के आधार पर निर्णय लेंगे और यह मार्गदर्शन नहीं देंगे कि हमें रुख बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि हम खुद निश्चित नहीं हैं कि इसके लिए कौन सी नीति कार्रवाई आवश्यक होगी।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की क्षिप्रा पेटकर से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करूँगा। क्षिप्रा, कृपया।

क्षिप्रा पेटकर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस:

शुभ दोपहर, गवर्नर। रिपोर्ट थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने ईसीबी के लिए स्वैप विंडो की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया है। आरबीआई इन अनुरोधों को कैसे देख रहा है, और क्या आपको लगता है कि विंडो की अवधि बढ़ाने की आवश्यकता है? धन्यवाद।

संजय मल्होत्रा:

मेरे विचार में कोई प्रस्ताव नहीं है जो विचाराधीन है, और दिए गए सुदृढ़ प्रवाहों के आधार पर, अभी न ही समय सीमा बढ़ाने की आवश्यकता है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं एएनआई के सौरभ मुखर्जी से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करूँगा। सौरभ, कृपया।

सौरभ मुखर्जी, एएनआई:

धन्यवाद, सर, मुझे अवसर देने के लिए। सर, मेरा आपसे प्रश्न है, बाहरी जोखिमों जैसे पश्चिम एशिया तनाव और कच्चे तेल की अस्थिरता के साथ, सीएडी को प्रबंधनीय स्तर पर अनुमानित किया गया है, आरबीआई को कितना विश्वास है कि पूंजी प्रवाह, विशेष रूप से एफडीआई और एफपीआई, इन झटकों को ऑफसेट करने के लिए पर्याप्त संरचनात्मक समर्थन प्रदान करेंगे? धन्यवाद, सर।

संजय मल्होत्रा:

जैसा कि मैंने कहा, मैक्रोइकोनॉमिक मूलभूत बातें बहुत मजबूत हैं और इसलिए, हमें अच्छे पूंजी प्रवाह जारी रखने चाहिए। एफडीआई निश्चित रूप से, अधिक स्थायी, अधिक अवरुद्ध और वरीय है। हमें अच्छे, मजबूत सकल एफडीआई संख्याएँ मिली हैं। यहाँ तक कि शुद्ध एफडीआई भी सकारात्मक है। सरकार कई चीजें कर रही है। एक तो व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए समझौतों की संख्या है, लेकिन यह भी अप्रत्यक्ष रूप से निवेश में मदद करता है, जो मदद करेगा। आगे चलकर, सरकार व्यवसाय करने में आसानी पर केंद्रित है, जो मदद करेगा। इसने एफडीआई के लिए विभिन्न क्षेत्रों के दायरे को खोला या विस्तारित किया है, उदाहरण के लिए, बीमा। तो, यह मदद करेगा।

हमने भी कई उपाय किए हैं। हम अब एफडीआई को शासित करने वाले नियमों, विनियमों को सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक मसौदा है, आप जानते हैं, जो सार्वजनिक परामर्श के तहत है। हम उन्हें सुव्यवस्थित करेंगे।

मुझे लगता है कि हमारी अर्थव्यवस्था की मूलभूत बातें बहुत मजबूत हैं। यहाँ तक कि यदि आप केवल पूंजी पक्ष पर ही नहीं, बल्कि चालू खाते के पक्ष पर भी देखें। इस वर्ष, पहले दो महीनों के लिए जिनके डेटा हमारे पास हैं, युद्ध के बावजूद, हमारे पास सीएडी अधिशेष है, जो पहले दो महीनों में बहुत अधिक है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन यदि आप पिछले वर्ष और इस वर्ष के पहले दो महीनों के बीच अंतर को देखें, तो चालू खाते में हम बेहतर हैं, और यह निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि निर्यात बेहतर किए गए हैं, आयात घट गए हैं। बहुत से आयात घट गए हैं। आगे चलकर, हम अपनी बाहरी स्थिति के बहुत अच्छे, उत्कृष्ट होने की उम्मीद करते हैं।

और जो उपाय हमने किए हैं, मुझे लगता है कि वे अपेक्षाओं के माध्यम से भी मदद करेंगे, जिसके कारण रुपये का अधिक प्रभाव दिखाई दिया। एफपीआई भी अधिकतर अपेक्षाओं पर आधारित है। जो एफपीआई प्रवाह अस्थिर रहे हैं, वे फिर से किसी अंतर्निहित कारण के कारण नहीं हैं, बल्कि मूल्यांकन, सापेक्ष मूल्यांकन के कारण हैं। लेकिन जैसा कि मैंने अपने वक्तव्य में भी उल्लेख किया, पहली तिमाही के परिणामों ने विनिर्माण और अन्य कॉर्पोरेट क्षेत्र का बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं आकाशवाणी के जीवन भवसार से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करूँगा। जीवन, कृपया।

जीवन भवसार, आकाशवाणी:

नमस्कार, सर। आपने अभी कहा कि प्लास्टिक नोट अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत तक बाजार में आ सकते हैं। तो, वर्तमान में, परीक्षण की स्थितियाँ क्या हैं, परीक्षण कहाँ शुरू हुआ है या होगा, और इसकी विशेषताएँ क्या होंगी? हम यह जानना चाहते हैं।

संजय मल्होत्रा:

हम आपको सही समय पर इसके बारे में सूचित करेंगे। वर्तमान में, हमने सब्सट्रेट के लिए एक टेंडर जारी किया है। उस सब्सट्रेट, पॉलिमर पेपर पर जिस पर यह नोट छपेगा, आने के बाद परीक्षण होगा, सुरक्षा स्पष्टीकरण किया जाएगा। कई चरण और कई सुरक्षा विशेषताएँ हैं। सही समय पर, हम आपको और सामान्य जनता को इसकी सुरक्षा विशेषताओं के बारे में सूचित करेंगे।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। मैं निक्केई के सौम्यजीत साहा से उनका प्रश्न पूछने का अनुरोध करूँगा। सौम्यजीत, कृपया।

सौम्यजीत साहा, निक्केई:

धन्यवाद, गवर्नर। पिछले वर्ष, सितंबर और दिसंबर के बीच, हमने देखा कि भारत के अमेरिका को निर्यात 1% से कम रहा, भले ही हम संपूर्ण एशिया में सबसे कठोर शुल्कों का सामना कर रहे थे। अब, अमेरिकी कांग्रेस द्वारा विचाराधीन रूस पर प्रतिबंध बिल है, भारत और चीन पर 100% तक के शुल्क का जोखिम है। दिए गए सौम्य - आर्थिक संवृद्धि पर अमेरिकी शुल्कों का पिछले वर्ष अपेक्षाकृत सौम्य प्रभाव, मैं समझना चाहता था, एक, अमेरिकी शुल्क आपके वर्तमान आर्थिक संवृद्धि के अनुमान के लिए कितने प्रासंगिक हैं? और दो, क्या आपके अनुभव के आधार पर, आपके हाल के अनुभव के आधार पर, अनुमान कम हो गया है, यदि बिल कानून में पारित हो जाता है तो?

संजय मल्होत्रा:

वर्तमान में, हमने वर्तमान शुल्कों के आधार पर अपने अनुमान दिए हैं। आगे चलकर, हम वास्तव में नहीं जानते हैं कि वे उच्च होंगे, वे कम होंगे। एक व्यापार समझौता भी हो रहा है, फिर वह बिल है जो पारित हो सकता है, और हम विचार करेंगे। मेरा मतलब है, यह अभी भी विकसित हो रहा है। यह निर्भर करेगा कि कौन से विशिष्ट क्षेत्र, किस प्रकार की दरें, आदि, हमारे प्रतिद्वंद्वी कौन हैं। यह बहुत सी बातों पर निर्भर करेगा। इसलिए, अभी, हमारे पास इसके बारे में किसी भी प्रकार के विश्लेषण के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है।

लेकिन आप सही कह रहे हैं कि चाहे हम हों या कोई और, शुल्कों का प्रभाव उतना नहीं है, क्योंकि कुछ पुनर्निर्देशन होता है। यदि आप अमेरिकी व्यापार डेटा को भी देखें, तो प्रभावी शुल्क दरें बहुत कम हैं, यदि आप बस शुल्कों को देखें, क्योंकि इतने सारे छूट - क्षेत्र छूट, देश छूट, और इसलिए स्पष्ट रूप से, प्रभाव हेडलाइन संख्याओं या शुल्कों के जैसा उच्च नहीं हो सकता है।

मनोजित साहा, बिजनेस स्टैंडर्ड:

आरबीआई अभी तक ऊपरी (लेयर एनबीएफसी) सूची जारी नहीं कर सका है। क्या आरबीआई ने अब ऊपरी (लेयर एनबीएफसी) सूची प्रकाशित न करने का निर्णय लिया है?

संजय मल्होत्रा:

अब, मुझे लगता है, यह अब सिद्धांत-आधारित है। इसलिए, उन सिद्धांतों के अनुसार, हर कोई जानता है कि सूची क्या है, और इसलिए यही वह स्थिति है, है ना?

शिरीष सी. मुर्मू:

हां, मुझे लगता है कि सूची बहुत जल्द जारी होगी, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, हमने नियम बदल दिए हैं। तो, क्या आपको सूची की आवश्यकता है?

संजय मल्होत्रा:

यही बात है, क्योंकि कोई भी, जिसका संपत्ति आकार एक विशेष सीमा से अधिक है - अब यह सरल है। आपको वास्तव में किसी से भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, सभी जानते हैं कि कौन सा एनबीएफसी ऊपरी लेयर में है, कौन सा मध्य लेयर में है, और कौन सा निम्न लेयर में है।

पीयूष शुक्ला, एनडीटीवी प्रॉफिट:

लोग सिर्फ उस एक के बारे में सोच रहे हैं जिसने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है।

संजय मल्होत्रा:

वह अभी भी बना हुआ है, सभी जो मानदंडों को पूरा करते हैं, वे बने रहते हैं।

पीयूष शुक्ला:

तो, टाटा सन्स सूची में बने रहेंगे?

संजय मल्होत्रा:

बने रहेंगे, यह सूची में है।

पीयूष शुक्ला:

नई सूची में जो जारी होगी?

संजय मल्होत्रा:

नई सूची, जैसा कि उल्लेख किया गया है, यह सिद्धांत-आधारित है, और यह जारी रहेगी। चलिए विशिष्ट संस्था से संबंधित विशिष्ट प्रश्न न पूछें। स्थिति वही है जो पहले थी।

एकता सूरी:

सर, मेरा प्रश्न यह था कि बैंकों के लिए, बढ़ाए गए आंकड़े दिखाना इतना बड़ा कारण बन गया है, मार्जिन इतनी बड़ी चिंता बन गए हैं कि कोई परिणाम घोषित करने से ठीक पहले अल्पावधि जमा लेता है ताकि सीएएसए अच्छा लगे, कोई एक ही ग्राहक को बल्क जमा के नाम पर मार्केटिंग खर्च के रूप में अतिरिक्त पैसे देता है, या कोई, ईसीएल के उत्साह में जहां अधिक प्रावधान करना है, जल्दी से खराब ऋणों को बही से बाहर निकाल लेता है। तो, क्या यह बैंकिंग क्षेत्र में एक प्रमुख चिंता बन गया है, जबकि लोगों के निवेश या अन्य चीजों के लिए विकल्प बढ़ रहे हैं और लोग बैंक में इतना पैसा रखना नहीं चाहते? तो, इन सभी चिंताओं को एक साथ लेते हुए, बैंक अपनी बुक्स को विभिन्न तरीकों से सजा रहे हैं। इस पर आरबीआई क्या कहेगी, सर?

संजय मल्होत्रा:

नहीं, मुझे नहीं लगता कि यह - जिसे आप विंडो-ड्रेसिंग कह रहे हैं - सबसे पहले, किसी को भी विंडो-ड्रेसिंग से कोई लाभ नहीं मिलता। यदि कोई बैंक या नियमित संस्था ऐसा करती है, तो आज सभी हितधारक, ग्राहक, सभी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि इस तरह की विंडो-ड्रेसिंग से न तो लाभप्रदता बढ़ती है, न ही उनकी बैलेंस शीट पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसलिए, सभी ग्राहक और हितधारक इसे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं।

इसलिए, उन्हें इससे कोई लाभ नहीं मिलता। मुझे नहीं लगता कि यह विंडो-ड्रेसिंग बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है या हम इसके बारे में चिंतित हैं। इस संबंध में हमारे निर्देश बहुत स्पष्ट हैं, और हमारी पर्यवेक्षण भूमिका - पर्यवेक्षक, वे भी समय-समय पर बैंकों की बुक्स और खातों की जांच करते हैं। और यदि उन्हें किसी ऐसे अवसर या मामले मिलते हैं, तो वे इसे सही करने के लिए निर्देश देते हैं। यह हमारे लिए एक विशेष चिंता नहीं है।

एकता सूरी:

लेकिन सर, जब यह नतीजों के आसपास होता है, यदि कोई शेयर खरीदना चाहता है, तो वे महसूस करते हैं कि नतीजे बहुत बढ़ाये गए हैं। तो, सर, क्या यह चिंता नतीजों के आसपास बढ़ जाती है?

संजय मल्होत्रा:

हमारी पर्यवेक्षण टीम जाती है और इन सभी चीजों की जांच करती है। यदि कोई इसे बार-बार कर रहा है, या आप जैसे कह रहे हैं, जब उनके नतीजे आ रहे हैं, तो इसकी जांच की जाती है। और कुछ - बहुत से नहीं, कुछ विनियमित संस्थाएं जो इस तरह से विचलित हैं। मैं डीजी श्री स्वामीनाथन से भी उत्तर देने का अनुरोध करूंगा।

स्वामीनाथन जे:

ठीक है, आपके द्वारा कहे गए बातों में संपूरक के रूप में, सर। मुझे लगता है कि आपने इतनी सारी चिंताओं की सूची बनाई है, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि तथ्य उतने बुरे नहीं हैं जितने आप उन्हें सूचीबद्ध करना चाहते थे। ऐसा नहीं है। मैं आपको बता सकता हूं कि प्रणाली मजबूत है, जैसा कि गवर्नर ने पहले उल्लेख किया था, और हमारे पास - एक तरफ, अच्छी तरह से जागरूक हितधारक हैं, और ऐसी परियोजना या छवि के साथ लंबे समय तक रहना आसान नहीं है जो अंतर्निहित स्थितियों की सही और निष्पक्ष स्थिति को प्रतिबिंबित नहीं करती है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि यह कुछ ऐसा है जो आपको लंबे समय तक समाधान दे सकता है।

दूसरा यह है कि हमारे पास - हमारे पास मजबूत पर्यवेक्षण है, जैसा कि गवर्नर ने उल्लेख किया, कि यदि किसी संस्था द्वारा कोई असामान्य व्यवहार दिखाया जाता है, तो हम उनके साथ द्विपक्षीय रूप से निपटते हैं, मीडिया के माध्यम से नहीं, लेकिन हम उनके साथ द्विपक्षीय रूप से निपटेंगे। इसलिए, आश्वस्त रहें कि, जैसा कि एमपीसी वक्तव्य में भी शामिल है, बैंकिंग प्रणाली के साथ-साथ एनबीएफसी क्षेत्र भी अर्थव्यवस्था में देखी जा रही अस्थिरता के बावजूद काफी लचीला है। लेकिन हम आगे भी हर एक नियमित संस्था से उभरने वाले डेटा बिंदुओं की निगरानी जारी रखेंगे, दोनों ऑन-साइट और ऑफ-साइट तरीकों के माध्यम से, और फिर यदि अनुपालन के किसी उदाहरण का पता चलता है, तो उसका निपटान करेंगे। लेकिन प्रणाली स्तर पर, आश्वस्त रहें कि चीजें पर्याप्त रूप से अच्छी तरह से प्रबंधित हैं।

मयूर शेटी:

सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई को मूल खातों से निपटने के लिए एसओपी जारी करने का आदेश दिया है। कोई टिप्पणी?

स्वामीनाथन जे:

हां, एक सुओ-मोटो मामला था, मुझे यकीन है कि आप सभी ने कल देखा होगा, आदेश जारी किया गया था, और एक मसौदा एसओपी पहले से ही तैयार किया गया है और सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। इसलिए, अब हम आरबीआई को दिए गए चार सप्ताह के समय के अनुसार उसे सुधारेंगे। इसलिए, हम सुप्रीम कोर्ट के अवलोकनों के आलोक में उसे सुधारेंगे, और हम जल्द ही जारी करेंगे।

और धोखाधड़ी की संख्या के साथ-साथ शिकायत निवारण मॉड्यूल, पैसे की वापसी मॉड्यूल सक्रिय होने के साथ, एक तरफ, धोखाधड़ी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी ओर, ग्राहक जागरूकता हमारे द्वारा और नियमित संस्थाओं द्वारा महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाई जा रही है। तीसरे पहलू में, जहां लोग पीड़ित बन गए हैं, वहां दोनों कानून प्रवर्तन और नियमित संस्थाएं उनके पैसे को जितना संभव हो सके वापस करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगी।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर।

संजय मल्होत्रा:

डीजी रोहित, क्या आपके पास कुछ जोड़ने के लिए है? यदि कोई ऐसी बात है जिसे मैंने छोड़ दिया है या जो आपसे संबंधित है जिसे आप पूरक बनाना चाहेंगे?

रोहित जैन:

तो, सामान्य रूप से मौद्रिक नीति में, सीबीडीसी और यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफ़ेस पर एक प्रश्न होता है, और आप में से कई लोग उसके तहत प्रगति के बारे में पूछ रहे हैं। तो, मैं बस यह बताना चाहता हूँ कि हम अच्छी प्रगति कर रहे हैं। अपनाने की दर बढ़ रही है। ये पायलट नहीं हैं, वे वास्तव में प्रारंभिक स्तर पर उपयोग किए जा रहे हैं। और हम बैंकों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि सीबीडीसी और यूएलआई दोनों के उपयोग के मामलों को बढ़ाया जा सके, और हम विभिन्न राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि यूएलआई के अपनाने को बढ़ाया जा सके। तो, आने वाले समय में, हम दोनों सीबीडीसी और यूएलआई के अधिक उपयोग और लोकप्रियता की उम्मीद करते हैं।

मनोजित साहा:

एक स्पष्टीकरण, जो यह है कि यदि पायलट सीबीडीसी समाप्त हो जाए तो?

रोहित जैन:

नहीं, नहीं, यह कभी पायलट नहीं था। यह वास्तव में हो रहा है। सीबीडीसी वास्तविक लेनदेन के लिए वास्तव में उपयोग किया जा रहा है। यह केवल नाम के लिए है कि यह एक पायलट है।

जसप्रीत कलरा, थॉमसन रॉयटर्स:

मुझे क्षमा करें यदि मैं इस पर स्पष्टीकरण दे सकता हूँ, सर, लेकिन क्या आप कह रहे हैं कि सीबीडीसी अब पायलट नहीं है? क्या यह पूर्ण रूप से तैयार है?

रोहित जैन:

नहीं, नहीं, यह पहले से ही वास्तविक लेनदेन के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसलिए, आप इसे इस तरह से पायलट नहीं कह सकते, लेकिन क्योंकि हम अभी भी तकनीक और विभिन्न अपनाने के तरीकों का परीक्षण कर रहे हैं, इसलिए इसे पायलट कहा जा रहा है।

हंसिनी कार्तिक, मनीकंट्रोल:

उपयोग का दायरा क्या है?

रोहित जैन:

विभिन्न उपयोग मामले हैं, दोनों अंतरराष्ट्रीय और विशिष्ट सरकारी योजनाओं, निर्देशित उपयोगों और विशिष्ट खंडों में अंतरण के लिए, ये सभी बढ़ाए जा रहे हैं जिससे अपनाने और उपयोग में वृद्धि होगी।

एकता सूरी:

और सर, यूएलआई के लिए, क्या रिकॉर्ड्स राज्य-वार भी डिजिटाइज़ किए गए हैं, ताकि उनका प्रवेश बढ़ सके?

रोहित जैन:

तो, अब तक 12 राज्यों ने अपने भूमि रिकॉर्ड्स डिजिटाइज़ किए हैं। अन्य राज्य भी यह काम कर रहे हैं। और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा सीबीडीसी और यूएलआई को विभिन्न योजनाओं के लिए उपयोग करने में बहुत रुचि दिखाई जा रही है। और हम उनके साथ लगातार संवाद कर रहे हैं ताकि उनके उपयोग में वृद्धि हो सके।

ब्रिज राज:

धन्यवाद, सर। इसके साथ, मैं गवर्नर, उप गवर्नर और मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और आप सभी को शुभ दिन की कामना करता हूं।
